(iii) The mails for Bulk recipients was to be sorted out and delivered through special staff if feasible other wise heads of InstitutesOffices receiving mail in bulk were to be requested to collect their mail at their own.

(iv) Sp>ecial arragements were made to deliver the communication (Admission forms, result sheets etc.) from College^ Universities addressed to students.

(v) Money Orders meant for student were transmitted on VSATESMOFAX network and delivered through special staff.

(vi) Speed Post articles were also delivered in the same nianner.

(vii) The Heads of Circles were authorised to engage outsider including students and retired officials for processing and delivery of mail.

(viii) New recruitsirainies were called for from training and their services were utilised for providing postal services.

(ix) Contractual vehicles were allowed to be utilised for conveyance of mails under Supervision of a responsible departmental official.

दूरसंचार विभाग को निगम के रूप में परिवर्तित किया जाना

4462. **श्रीमती सरोज दुवे**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरसंचार विभाग को निगम के रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कार्यरत कर्मचारियों की सेवा में भी कोई परिवर्तन किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उपका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ अभरती हुई प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावी ठंग से सामना करने के लिए इसकी कार्यकारी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए मुक्यत: नीतिनिर्माण तथा लाइसेसिंग कार्यों के प्रचालनात्मक कार्यों से अलग करने के संबंध में दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) का पुनर्गठन करने के मामले की जांच की जा रही है। पिछले वर्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण की स्थापना को भी नीति निर्माण तथा लाइसेंसिंग कार्यों को प्रचालनात्मक कार्यों से अलग करने की दिशा में एक तर्क संगत कदम माना जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि, कुछ वर्ष पूर्व, भावी प्रचालनात्मक तथा विकासात्मक आवश्यकतओं को ध्यान में रखते हुए देश में दूरसंचार संवाओं के प्रबंध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे के बारे में सिफारिश करने के लिए डा. अभय, एक जाने माने प्रबंध विसेषज्ञ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने (जिसने मार्च, 1991 में अपनी निपोर्ट प्रस्तुत की) किसी भी संशोधित संरचना में "नीति तथा नियमन" टियर को "प्रचालन" (आपरेशन) टियर से अलग करने की आवश्यकता को स्वीकार किया लेकिन समिति इस विभाग के भावी संगठन के आकार के वारे में एकमत नहीं थी।

तदनुसार, 1995 में डीआटा मुख्यालय की पुनसंरचना के बारे में सिफारिश करने के लिए श्री डी.के. गुप्ता, सेवानिवृत संदस्य (सेवाएं) दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान समिति ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारी संषों के प्रतिनिथियों से मुलाकात की और अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की कि डी ओ टी को दो स्पष्ट रूप से परिभावित निकायों में विभाजित कर दिया जाए एक निकाय नीति तथा योजना तौयार करने के लिए तथा दूसरा दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य करने के लिए जिसे " इंडिया टेलीका म" कहा जा सकता है।

डी के. गुप्ता समिति ने यह भी निफारिश की कि स्वतंत्र मूल्य एवं लाभ केन्द्रों के रूप में सर्किलों/जिलों के साथ-साथ "इंडिया टेलीकाम" को एक निगमित निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। इस रिपोर्ट के और आगे जांच की गई और इस बात पर सहमति हुई कि दूरसंचार विभाग के प्राचलन कार्यों को लाइसेंसिंग तथा नीति कार्यों से अलग किया जाए ताकि को डेडिकेटेड मैनेजमेंट इनपुट्स प्रदान किया जा सके तथा सभी दरसचार प्रचालकों को लेवल-प्लेईग फील्ड प्रदान किया जा सके।

हाल के महीनों में, इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न यूनियनों तथा स्टाफ संघोंके साथ चर्चा की गई है। प्रस्तावित पुरसैचना तथा इससे जुड़े जटिल मुद्दों के संबंध में जबकि अनेक विचार एवं मत दिये गये हैं,

निगम बनाने के विकल्प का अनुसरण करने के साथ-साथ डी ओ टी का तर्क संगत पुनगर्ठन करने तथा इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में व्यापक सर्व सहमति पाई गयी है। इनके बारे में (तथा इससे जुड़े मुद्दे के बारे में) व्यापक अध्ययन करने तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिसकी विधिवत शुरुआत कर दी गई है।

Revenue Sharing Between Basic Service Operators and DoT.

4464. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have issued any guidelines or put any conditions like revenue sharing between basic service operators and the Department of Telecommunications, during fourth round of bidding in respect of eight circles, as reported in the Economic Times, New Delhi Edition, dated 4th July, 1998;

(b) if so, the details thereof indicating demands of cellular operators and reaction of Government thereto; and

(c) what steps Goverment have taken so far for telecom expansion will full transparency and targets set in this regard during 1998-99?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of 'a' above. However, the cellular operators have demanded a moratorium on the payment of Licence Fee and extension of the licence period. The matter has been referred to the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) and their reptort is awaited.

(c) The targets set for various Telecom Services for 1998-99 are as given below:—

(i)	New Switching Capacity	—49.3	lakh lines
(ii)	Direct Exchange Lines	— 36	lakh lines
(iii)	Tax Capacity	— 4.5	lakh lines
(iv)	Microwave45ftF	—	19500 Rkms.
(V)	Optical Fibre	—	35000 Rkms.
(vi)	VPTs	—	45000 Nos.

Requests to Provide Certain Equipment to the A.P. Telecom Circle International Airports

4465. DR. Y. LAKSHMl PRASAD: Will the Minister of COMMUNICA TIONS be pleased to state:

(a) whether requests have beein received to provide certain equipment to the A.P. Telecom Circle for early implementation of the State wide area network in Andhra Pradesh; and

(b) if so, the action taken to supply necessary equipments to remove encroachments and improve roads infrastructure in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) and (b) Yes, Sir. Request had been received for allotment of certain store items to remove encroachments and improve roads infrastructure in Andhra Pradesh Telecommunication Circle. Most of the store items have been allotted and material received under Mission Better communication and development works are also being diverted for these works.

Steps to Motivate Private Operators in Rural Areas

4466. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Telecom Policy, 1994, sought to attract private sector investment of Rs. 23,000 crore for providing basic telephone services in competition with DoT;

(b) if so, the steps Government has taken or plans to motivate the private